अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या:1419-1420/2012)

(फ़रवरी 20, 2014)

[के.एस. राधाकृष्णन और विक्रमजीत सेन, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302, 377 और 201 - सोडोमी, बदमाशी और पाशविकता - हत्या - 10 साल की उम्र के नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई - दोषसिद्धि और मौत की सजा - अपील पर, आयोजित: अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य यह पूरी तरह से भरोसेमंद और भरोसेमंद है - आरोपी की बहन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने आधी रात के दौरान आरोपी के कमरे से पीड़ित-मृतक की चीखें सुनी थीं और जब तक चीखें कम नहीं हुईं तब तक वह सो नहीं पाई - उसके पास खुद पर हमला करने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी अपना भाई था और एक भरोसेमंद गवाह था - मृतक का स्कूल बैग और पैंट आरोपी के घर में खाट के नीचे रखे एक बक्से से बरामद किया गया था, जिससे संकेत मिलता है कि मृतक उस रात आरोपी के साथ था - डीएनए परीक्षण से भी यह साबित हुआ कि गुदा स्मीयर का मिलान स्मीयर के धब्बों के डीएनए प्रोफाइल से हुआ, जो आरोपी के

नियंत्रण रक्त के नमूने से भी मेल खाता है - एक निष्क्रिय एजेंट की सहमति बिल्कुल भी बचाव नहीं थी, वह नाबालिग था - लड़के को पेडरैस्टी के अधीन करने के बाद अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि , उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई - धारा 302, 377 और 201/पीसी के तहत मामला स्पष्ट रूप से सामने आया - आरोपी ने 35 साल की उम्र में अपराध किया और वह पूरी तरह से परिपक्व व्यक्ति था - उसके पक्ष में कोई भी कम करने वाली परिस्थिति नहीं थी - कुछ भी नहीं था यह दिखाने के लिए कि वह किसी भावनात्मक या मानसिक तनाव में था - अपराध केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए, विकृत तरीके से किया गया था - हत्या बेहद क्रूर, वीभत्स, शैतानी और कायरतापूर्ण तरीके से की गई थी और आरोपी हावी स्थिति में था और पीड़ित एक मासूम लड़का था - एक लड़के का जीवन, अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य 35 अपनी मां के इकलौते बेटे को छीन लिया गया, जो न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज के विवेक को भी चुभता है - पहले से ही भुगती गई सजा के अलावा, बिना छूट के तीस साल की अतिरिक्त कैद पर्याप्त होगी मौत की सज़ा के बजाय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सज़ा - सज़ा/सज़ा।

चिकित्सा न्यायशास्त्र: डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीएनए - का साक्ष्य मूल्य - माना गया: डीएनए एक अणु है जो सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध करता है - डीएनए जीनोटाइप किसी भी जैविक सामग्री जैसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल से प्राप्त किया जा सकता है। त्वचा, आदि -आम तौर पर, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का डीएनए प्रोफाइल संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, तो आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति एक ही है - डीएनए प्रोफाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन भिन्नता है किसी विशेष परिणाम में प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करता है - दंड संहिता, 1860 - साक्ष्य।

सज़ा/सज़ा:

दुर्लभ से दुर्लभ मामला -आयोजित: आर-आर परीक्षण समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है न कि "न्यायाधीश-केंद्रित': यानी, क्या समाज कुछ लोगों को मौत की सज़ा देने को मंजूरी देगा या नहीं अपराधों के प्रकार या नहीं - उस परीक्षण को लागू करते समय, अदालत को कुछ प्रकार के अपराधों जैसे कि यौन उत्पीड़न और नाबालिग लड़कियों की हत्या, बौद्धिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़कियों, पीड़ित नाबालिगों के प्रति समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और घृणा जैसे विभिन्न कारकों पर गौर करना होगा। शारीरिक विकलांगता, वृद्ध और

अशक्त महिलाएँ, आदि - वर्तमान मामले में, धारा 377 के तहत अपराध पूरी तरह से साबित हुआ, इसलिए धारा 302 के तहत अपराध भी पूरी तरह से साबित हुआ - भारतीय समाज और जी अंतर्राष्ट्रीय समाज भी अप्राकृतिक यौन संबंध से घृणा करता है। यानी एक पुरुष और एक नाबालिग लड़के या लड़की के बीच शारीरिक संबंध - जब पीड़ित नाबालिग है, तो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध पर कुछ हलकों में व्यक्त विचारों के बावजूद, सहमति बचाव नहीं है।

36 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

सुधार और पुनर्वास - सजा का निर्धारण - अदालतों का कर्तव्य - माना गया: यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि क्या आरोपी समाज के लिए खतरा होगा और सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं होगी और 'राज्य इसके लिए बाध्य है अभियुक्तों के सुधार और पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करें।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 235(2) आरएल डब्ल्यू धारा 354(3) -मृत्युदंड -सुनाया गया: जब दोषी भ्रष्टता के अनुपात को मान लेता है, तो न्यायालय को धारा 354(3) के अर्थ के भीतर विशेष कारण बताने पड़ते हैं मौत की सजा देना - विधायी नीति यह है कि जब विशेष कारण मौजूद हों, जैसे कि तत्काल मामले में। न्यायालय को अपने

संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा और उचित सजा देकर विधायी नीति का सम्मान करना होगा, जो लोगों की इच्छा है - सजा/दंड।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी-अपीलकर्ता ने 10 साल की उम्र के एक नाबालिग लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302, 377 और 201 के तहत दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और मौत की सजा की पुष्टि की। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपीलें दायर की गईं।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

अभिनिर्धारित किया : 1. पीडब्लू 2, पीडब्लू 3, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 9 के साक्ष्य पूरी तरह से भरोसेमंद और विश्वसनीय थे। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सफल रहा कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। मृतक के पैंट के साथ-साथ स्कूल बैग की बरामदगी को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू 1 और पीडब्लू 6 की जांच की गई। स्कूल बैग बरामद कर लिया गया

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य 37 एक बक्से से जो आरोपी के घर में खाट के नीचे रखा गया था। स्कूल बैग में किताबें और नोट बुक थीं जिन पर मृतक का नाम लिखा था। पैंट और स्कूल बैग के साथ-साथ उसमें मौजूद किताबों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि लड़का उस दिन आरोपी के साथ था। नतीजतन, आरोपी के कमरे में मृतक की उपस्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई और ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा उस आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्ष में भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 11,12) [51-जी-एच; 52-ए-डी]

2. पीडब्लू4, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि सभी आंतरिक चोटें बाहरी चोटों से मेल खाती हैं और वे मृत्यु-पूर्व थीं और आमतौर पर मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। पीडब्लू4 ने यह भी राय दी कि मृतक के साथ शारीरिक संबंध बनाने की संभावना थी, हालांकि मौत का कारण सिर पर चोट थी। पीडब्लू 4 के अनुसार, डीएनए रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक के गुदा स्मीयर से एक मिश्रित डीएनए प्रोफ़ाइल मिली, जो हाफ पैंट पर लगे वीर्य और पीड़ित के खून से मेल खाती थी। पीडब्लू4 को डीएनए की एक अन्य रिपोर्ट भी दिखाई गई, जो आरोपी के नियंत्रण नमूने के रक्त के संबंध में थी और कहा गया कि रक्त का डीएनए प्रोफाइल मृतक के गुदा में पाए गए वीर्य के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि चोट नं.

1, 3, 4 और 5 कठोर और कुंद वस्तु के कारण संभव थे जबकि चोट संख्या 2 तेज धार वाली धार के कारण हुई थी और चोट संख्या 6 कठोर और खुरदरी वस्तु के कारण हुई थी। तथ्यों से साफ पता चलता है कि बर्बर तरीके से हवस पूरी करने के बाद उसे चुप कराने के लिए जानलेवा चोटें पहुंचाई गईं। सबूत मिटाने की कोशिश की गई जो साबित भी हुए. पीडब्लू4 ने चोट संख्या 1 के संबंध में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे गुदा के फैलाव के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और तालु जैसा दिखाई देना चाहिए, पेरिअनल मार्जिन गुदा म्यूकोसा में सूजन दिखाई देती है, हालांकि आंसू या विदेशी शरीर का कोई सबूत नहीं है। [पैरा 13,14] [52-ई; 53 एफ-एच; 54-ए-बी]

38 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

3. पीडब्लू 5, सहायक रासायनिक विश्लेषक, फोरेंसिक साइंस लैब ने कहा कि Exh.1 आरोपी का डीएनए प्रोफ़ाइल था और Exh.5 गुदा स्मीयर मृतक का था, जो मिश्रित प्रोफ़ाइल देता था। उसने कहा कि उसने दो परीक्षण किए, एक न्यूक्लियर शॉर्ट टैंडेम रिपीट (एसटीआर) और वाई शॉर्ट टैंडेम रिपीट (वाईएसटीआर)। पीडब्लू 5 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने अभियुक्तों के रक्त के नमूने प्राप्त किए और उस रक्त से प्राप्त प्रोफ़ाइल का Exhs.1 और 5 की प्रोफ़ाइल से मिलान किया और प्रोफ़ाइल मेल खा रही थी। पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 के साक्ष्य को पीडब्लू 12, पीडब्लू 15 और

पीडब्लू 16 के साक्ष्य के साथ पढ़ा गया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि डीएनए परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था और गुदा स्मीयर वीर्य के दाग के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता था जो आरोपी की पैंट पर पाए गए थे और उनसे मिलान किया गया था। अभियुक्त के रक्त के नमूने के साथ-साथ मृतक के रक्त के नमूने को भी नियंत्रित किया गया। [पैरा 15,16) [54-सी-एफ; 55-ए-बी]

4. डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीएनए, एक अणु है जो सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध करता है। डीएनए जीनोटाइप किसी भी जैविक सामग्री जैसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अब, कई वर्षों से, डीएनए प्रोफ़ाइल ने फ़क्रेन्सिक जांच पर भी जबरदस्त प्रभाव दिखाया है। आम तौर पर, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का डीएनए प्रोफाइल संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, तो आमतौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति समान है। डीएनए प्रोफ़ाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष परिणाम में भिन्नता प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करती है। पीडब्लू 5 ने कहा कि 1994 से वह सहायक रासायनिक विश्लेषक के रूप में काम कर रही थी और उसने डीएनए परीक्षण सहित हजारों नमूनों का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दो परीक्षण किए थे, एक एसटीआर और दूसरा वाईएसटीआर। दोनों परीक्षण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध थे

और परीक्षण करने वाले डॉक्टर की क्षमता पर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया था। नतीजतन, डीएनए परीक्षण रिपोर्ट हो सकती है

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य 39 सुरक्षित रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे पता चला कि मृत लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया था और धारा 377 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। [पैरा 17,18] [55-सी-एफ]

5. धारा 377 मुख्य रूप से लौंडेबाज़ी, गुंडागर्दी और पाशविकता के कृत्य तक ही सीमित है, जिसका उद्देश्य किसी पुरुष को दंडित करना है जब वह किसी पुरुष के साथ या उसी तरह, एक महिला के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है। सोडोमी को पेडरैस्टी कहा जाता है जब संभोग एक पुरुष और एक युवा लड़के के बीच होता है, यानी जब निष्क्रिय एजेंट एक युवा लड़का होता है। मोदी के मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान में कहा गया है कि यदि कोई निष्क्रिय एजेंट सोडोमी का आदी नहीं है, तो गुदा के पास की त्वचा पर घर्षण दिखाई देने की संभावना है और घाव बच्चों में सबसे अधिक चिह्नित होंगे, जबकि वे वयस्कों में लगभग अनुपस्थित हो सकते हैं, जब कोई प्रतिरोध नहीं होता है गुदा मैथुन के लिए. गैल्स्टर के मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान का कहना है कि निष्क्रिय एजेंट में हालिया घाव, चोट, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन जैसे घाव देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 377 लिंग द्वारा गुदा में प्रवेश को दर्शाता

है और अपराध स्थापित करने के लिए मामूली प्रवेश ही पर्याप्त है। पीडब्लू 4 ने स्पष्ट रूप से देखा है कि "गुदा चौड़ा हो जाता है और पाताल जैसा दिखाई देता है, पेरिओनल मार्जिन और म्यूकोसा सूजा हुआ दिखाई देता है"। डीएनए परीक्षण से यह भी साबित हुआ कि गुदा स्मीयर स्मीयर के दाग के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, जो आरोपी के नियंत्रण नमूने से भी मेल खाता है। एक निष्क्रिय एजेंट की सहमति बिल्कुल भी बचाव नहीं है, लेकिन, मौजूदा मामले में, हालांकि एक सुझाव दिया गया था कि लड़के ने विरोध नहीं किया था, कुछ दिनों के लिए आरोपी की कंपनी में रहने का कोई मतलब नहीं है, वह एक है नाबालिग। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि, लड़के को पेडरैस्टी के अधीन करने के बाद, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। [पैरा जी 19] [55-जी-एच; 56-ए-डी]

6. पीडब्ल्यूएस, आरोपी की बहन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने आधी रात के दौरान आरोपी के कमरे से लड़के की चीखें सुनी थीं और जब तक चीखें कम नहीं हुईं, उसे नींद नहीं आई। उसके पास शिकायत करने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी

40 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

अभियुक्त और एक विश्वसनीय गवाह था. पीडब्लू9 ने यह भी कहा कि वह उस दिशा में जाना चाहती थी जहां उसने चीखें सुनी थीं, हालांकि, अंधेरे ने उसे और अन्य लोगों को घटनास्थल की ओर बढ़ने से रोक दिया।

सुनाई देने वाली चीखें स्पष्ट रूप से तेज़ आवाज़ में थीं, जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी ने इस तरह के बर्बर कृत्य में शामिल होकर अंततः लड़के को मार डाला और बाद में शव को पुराने कब्रिस्तान के परिसर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया, जो कि पीछे स्थित एक स्थान था। उसके घर। इसलिए, नीचे की अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध मानसिक रूप से अत्यधिक भ्रष्टता दर्शाता है और अत्यधिक विकृति दर्शाता है और इसलिए, अत्यधिक दंड की मांग की जाती है यानी अभियुक्त को तब तक गर्दन से फाँसी दी जानी चाहिए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 302, 377 और 201 के तहत मामला बनाया गया था। मौजूदा मामले में अपराध परीक्षण और फौजदारी परीक्षण में आरोपी के खिलाफ पूरी तरह से संतुष्टि हो चुकी है। [पैरा 20,21) [56-ई-एच; 57-ए और डी]

7. पेडेरास्टी से पहले हुए अपराध बेहद क्रूर, विचित्र शैतानी और विद्रोही हैं, जो समाज के नैतिक ढांचे को झकझोर देते हैं, खासकर जब निष्क्रिय एजेंट नाबालिग हो। आरोपी की उम्र अब करीब 42 साल है और जब उसने अपराध किया तब उसकी उम्र करीब 35 साल थी. अभियुक्त के पक्ष में कोई शमनकारी परिस्थिति नहीं है। उम्र उनके पक्ष में कोई कारक नहीं है. 35 वर्ष की आयु तक, एक व्यक्ति पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर लेता है और यह पहचान सकता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा, और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह किसी भी भावनात्मक या

मानसिक तनाव में था और अपराध केवल विकृत तरीके से अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। . आरोपी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा नहीं है, लेकिन लड़का नाबालिग, पूरी तरह से निर्दोष और असहाय था, पीडब्ल्यू 7 का इकलौता बेटा था। माँ, पीडब्लू7 एक घरेलू नौकरानी थी और बेटा बुढ़ापे में उसकी देखभाल करता था और उसकी काफी मदद भी करता था। आरोपियों की विकृत हवस को पूरा करने के लिए ही उसके बेटे को बर्बरतापूर्वक वीभत्स तरीके से छीन लिया गया। पीडब्लू7, माँ को का शव देखना पड़ा

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य 41 वह बेटा कुएं में तैर रहा है। पीडब्लू8, आरोपी ए की बहन और पीडब्लू9, पड़ोसी, दोनों महिलाओं ने आधी रात के दौरान असहाय लड़के की चीखें सुनीं लेकिन दोनों असहाय थीं। पीडब्लू 8 अपने कमरे से बाहर नहीं जा सका क्योंकि वह बाहर से बंद था। पीडब्लू9, एक महिला घने अंधेरे के कारण आरोपी के घर नहीं जा सकी। लेकिन, जहां तक तत्काल मामले का सवाल है, धारा 302 और 377 के तहत अपराध पूरी तरह से स्थापित थे और अपराध परीक्षण और आपराधिक परीक्षण दोनों आरोपी के खिलाफ पूरी तरह से संतुष्ट थे। [पैरा 21 से 24] [57-ई-एफ, जी-एच; 58-ए-ई]

शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एससीसी 546; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684: 1980

एआईआर 898; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470: 1983 (3) एससीआर 413; सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य (2014) 1 एससीसी 1: 2014 एआईआर 563 -पर भरोसा किया गया।

आरआर टेस्ट

8. आर-आर टेस्ट समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है न कि "न्यायाधीश-केंद्रित", यानी कि क्या समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने को मंजूरी देगा या नहीं। उस परीक्षण को लागू करते समय, अदालत को नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न और हत्या, बौद्धिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़कियों, शारीरिक विकलांगता से पीड़ित नाबालिगों, वृद्ध और अशक्त जैसे कुछ प्रकार के अपराधों के प्रति समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और घृणा जैसे विभिन्न कारकों पर गौर करना होगा। महिलाएं, आदि। इस मामले में आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध पूरी तरह साबित हुआ और धारा 302 आईपीसी के तहत भी अपराध साबित हुआ। भारतीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय समाज भी पांडित्य, एक अप्राकृतिक जी सेक्स, यानी एक पुरुष और एक नाबालिग लड़के या लड़की के बीच शारीरिक संबंध से घृणा करता है। जब पीड़िता नाबालिग हो, तो सहमति बचाव नहीं है, भले ही वयस्कों

के बीच सहमति से यौन संबंध पर कुछ हलकों में जो भी विचार व्यक्त किए गए हों। [पैरा 26,29] [59-एच; 60-ए-बी; 61-बी]

42 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014) 3 एस.सी.आर.

ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (1999) 3 एससीसी 19: 1999 (1) एससीआर 794; यूपी राज्य वी. सत्तन (2009) 4 एससीसी 736: 2009 (3) एससीआर 643; संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498: 2009 (9) एससीआर 90; बंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 11 सेकंड 113 : 2008 (11) एससीआर 184; शिवाजी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 15 एससीसी 269: 2008 (13) एससीआर 81; मो. मन्नान बनाम बिहार राज्य (2011) 5 एससीसी 317: 2011 (5) एससीआर 518; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 4 एससीसी 37: 2012 (2) एससीआर 225; हरेश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 12 एससीसी 56: 2011 (14) एससीआर 921; रवीन्द्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम रिपब्लिक। भारत का (2011) 2 एससीसी 490: 2011 (1) एससीआर 929; सुरेंद्र कोफ़ी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 4 एससीसी 80: 2011 (2) एससीआर 939; सुदाम @ राहु/ कनीराम जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 7 एससीसी 125: 2011 (6) एससीआर 1104; महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1987) 3 एससीसी 80: 1987 (2) एससीआर 710; सेवक

पेरुमल बनाम टी.एन. राज्य (1991) 3 एससीसी 471: 1991 (2) एससीआर 711; महा राज्य. बनाम मानसिंह (2005) 3 एससीसी 131: 2001 (4) पूरक। एससीआर 298; बंटू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2001) 9 एससीसी 615: 2006 (10) सपोर्ट एससीआर 662 -पर भरोसा किया गया।

सुधार और पुनर्वास

9. कई बार, सजा का निर्धारण करते समय, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए यह मान लेती हैं कि आरोपी समाज के लिए खतरा होगा और सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। जबकि उन कारकों का पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है, और राज्य अभियुक्तों के सुधार और पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। किसी दिए गए मामले में अदालतें जिन तथ्यों पर विचार करती हैं, वे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। आपराधिक अदालतें, आईपीसी की धारा 302 जैसे अपराधों से निपटते समय, दोषसिद्धि के बाद, उचित मामलों में, यह निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट मांगने का निर्देश दे सकती हैं,

अनिल @एंथनी अरिक्सस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य 43

क्या अभियुक्त को सुधारा जा सकता है या उसका पुनर्वास किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। [पैरा 31] [61-एफ-एच; 62-ए]

10. पीडब्लू 8 और पीडब्लू 9 ने 12,01.2008 की मध्यरात्रि के दौरान नाबालिग लड़के की रोने की आवाज़ सुनी। चोट संख्या 1, 3 से 5 कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं, जबकि चोट संख्या 2 तेज धार वाली धार से लगी थीं और चोट संख्या 6 कठोर और दाने वाली वस्तु से लगी थीं, इसके अलावा, धारा 377 के तहत भी अपराध हुआ। साबित हुआ. हत्या बेहद क्रूर, वीभत्स, शैतानी और नृशंस तरीके से की गई थी और आरोपी दबंग स्थिति में था और पीड़ित एक निर्दोष लड़का था। अपराध को अंजाम देने के समय आरोपी की उम्र 35 साल थी यानी वह पूरी तरह से परिपक्व व्यक्ति था। एक लड़के, पीडब्लू7 के इकलौते बेटे, मां, की जान वीभत्स और बर्बर तरीके से छीन ली गई, जो न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज के विवेक को भी चुभता है। विधायी नीति सीआरपीसी की धारा 354(3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 235(2) से समझ में आती है, कि जब दोष भ्रष्टता के अनुपात को मान लेता है, तो न्यायालय को धारा 354(3) के अर्थ में विशेष कारण बताने पड़ते हैं। मौत की सज़ा का. विधायी नीति यह है कि जब विशेष कारण मौजूद होते हैं, जैसे कि तत्काल मामले में, न्यायालय को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है और उचित सजा देकर विधायी नीति का सम्मान करना होता है,

यही लोगों की इच्छा है। पहले से भुगती गई सजा के अलावा, बिना किसी छूट के तीस साल की अतिरिक्त अवधि की कैद, मौत की सजा के बजाय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पर्याप्त सजा होगी। [पैरा 33,34] [62-ई-एच; 63-ए-सी]

आलोक नाथ दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2007) 12 एससीसी 230: 2004 (1) पूरक। एससीआर 918; सहदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 10 एससीसी 682: 2007 (7) एससीआर 616; स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 12 एससीसी 288;

44 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

शंकर किसनराव खाड़े (सुप्रा), हरेश मोहनदास राजपूत (सुप्रा), राजेश कुमार बनाम राज्य (2011) 13 एससीसी 706; अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 सेकंड 101: 2012 (1) एससीआर 1009 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

2013 (5) sec 546	relied on	Para 21
1980 AIR 898	relied on	Para 21
1983 (3) SCR 413	relied on	Para 21
2014 AIR 563	relied on	Para 22
1999 (1) SCR 794	relied on	Para 25

2009 (3) SCR 643 relied on Para 25

2009 (9) SCR 90 relied on Para 25

2008 (11) SCR 184 relied on Para 26

2008 (13) SCR 81 relied on Para 26

2011 (5) SCR 518 relied on Para 26

2012 (2) SCR 225 relied on Para 26

2011 (14) SCR 921 relied on Para 27

2011 (1) SCR 929 relied on Para 27

2011 (2) SCR 939 relied on Para 27

2011 (6) SCR 1104 relied on Para 27

1987 (2) SCR 710 relied on Para 28

1991 (2) SCR 711 relied on Para 28

2005 (3) sec 131 relied on Para 32

2001 (4) Suppl. SCR 298 relied on Para 32

2006 (10) Suppl. SCR 662 relied on Para 32

अनिल @एंथनी अरिक्सस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य 45

2004 (1) Suppl. SCR 918 Referred to Para 32

2007 (7) SCR 616 Referred to Para 32

(2007) 12 sec 288 Referred to Para 32

(2011) 13 sec 706 Referred to Para 32

2012 (1) SCR 1009 Referred to Para 32

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1419-1420/ 2012।

आपराधिक पुष्टिकरण मामले संख्या 2/2011 के आपराधिक अपील संख्या 17/2010 में बॉम्बे के सी उच्च न्यायालय, नागपुर की नागपुर पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 18.10.2011 से।

पी.सी. अपीलकर्ता की ओर से अग्रवाल, रेवती राघवन।

प्रतिवादी की ओर से शंकर चिल्लागे (आशा गोपालन नायर के लिए)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

के.एस. राधाकृष्णन, जे.

1. इस मामले में, हम 10 साल की उम्र के एक नाबालिग लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने और फिर उसका गला घोंटकर नृशंस हत्या करने से चिंतित हैं।

2. आरोपी अनिल उर्फ एंथोनी अरिक्सस्वामी जोसेफ पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 377 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, नागपुर ने 2008 के सत्र परीक्षण संख्या 167 में अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने और डिफ़ॉल्ट रूप से भुगतने की सजा भी सुनाई। अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास। आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय, उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई और डिफ़ॉल्ट के रूप में तीन महीने की अवधि का कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई।

46 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था और उसे 3 साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी और डिफ़ॉल्ट रूप से तीन महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई थी। यह आदेश दिया गया था कि मूल वाक्य एक साथ चलेंगे। चूंकि अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई गई थी, इसलिए मौत की सजा की

पुष्टि के लिए संदर्भ उच्च न्यायालय को भेजा गया था। अभियुक्त ने 2011 की आपराधिक अपील संख्या 17 भी दायर की।

3. अपील और आपराधिक पुष्टिकरण मामला 10.08.2011 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया और बेंच ने देखा कि डीएनए प्रोफाइल रक्त का नमूना और वीर्य का नमूना ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मुंबई के सहायक रासायनिक विश्लेषक पीडब्लू5 ने एक्सटेंशन 35 की सामग्री के संबंध में विस्तृत साक्ष्य दिए थे। उसने कहा कि उसे आरोपी के रक्त के नमूने के डीएनए की तुलना Ext.1 (हाफ पैंट पर वीर्य के धब्बे) और Ext.5 (मृतक के गुदा का धब्बा) से करने का अवसर मिला और DNA नमूने मेल खा रहे थे। पीडब्लू 5 ने प्रस्तुत किया Ext.38 रिपोर्ट. Ext. 38, यह देखा गया, किसी भी तुलना अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी के खिलाफ पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, अदालत ने महसूस किया कि पीडब्लू 5 को वापस बुलाना और उसकी रिपोर्ट के संदर्भ में उसकी आगे की जांच को रिकॉर्ड करना आवश्यक होगा। अभियुक्त की डीएनए प्रोफ़ाइल के संबंध में, वह भी 25.09.2009 को उसके मुख्य परीक्षण के पैराग्राफ संख्या 3 में उसके साक्ष्य के संदर्भ में।

4. इसलिए, बेंच ने अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

(i) 1997 के सत्र परीक्षण संख्या 118 और 2002 के सत्र परीक्षण संख्या 39 में निर्णयों की प्रतियों के उत्पादन के लिए प्रार्थना टिक नहीं पाती है क्योंकि यह ए दबाया नहीं गया है।

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य[के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 47

(ii) अभियोजन पक्ष अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट का रुख करेगा।

(iii) अभियोजन पक्ष P.W.5 को वापस बुलाएगा और आरोपी के रक्त के नमूने के डीएनए प्रोफाइल के संदर्भ में उक्त गवाह की दोबारा जांच करेगा और रिपोर्ट Exibits.35 के Exibits.1, 4 और 5 के साथ उसकी तुलना करेगा।

(iv) विद्वान ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष को साक्ष्य से जुड़े या नमूनों के संग्रह से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज को एफ.एस.एल. में ले जाने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा। और उसका विश्लेषण।

(v) विद्वान ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष को नमूनों के संग्रह से संबंधित किसी अन्य गवाह की जांच करने की अनुमति देने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसे एफ.एस.एल. में ले जाया जाएगा। और उसका विश्लेषण।

(vi) अभियोजन पक्ष P.W.10 और P.W.14 को वापस बुलाएगा और Exibit.35 के नमूने Exibit.1, 4 और 5 और आरोपी-अपीलकर्ता के रक्त और वीर्य के नमूनों को अग्रेषित करने के संदर्भ में उनकी आगे की जांच करेगा।

(vii) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी-अपीलकर्ता को इस आदेश के बाद वापस बुलाए गए गवाहों या जांचे गए नए गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाएगा।

(viii) यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट इस आदेश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी आकस्मिक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन यह देखने के लिए सावधान रहेगा कि अभियोजन पक्ष पेश करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के इस अवसर का दुरुपयोग न करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट इस आदेश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी आकस्मिक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन यह देखने के लिए सावधान रहेगा कि अभियोजन पक्ष किसी अन्य

साक्ष्य को पेश करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के इस अवसर का दुरुपयोग न करे, जो वर्तमान आदेश का विषय नहीं है।

(ix) मूल रिकॉर्ड और कार्यवाही विद्वान सत्र न्यायाधीश, नागपुर को वापस भेजी जाए।

(x) विद्वान सत्र न्यायाधीश इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन करेंगे और अतिरिक्त साक्ष्य को तुरंत इस न्यायालय को प्रमाणित करेंगे।

तदनुसार आवेदन का निपटारा किया जाता है।"

5. सत्र न्यायालय ने, आदेश के अनुसार, अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने और गवाहों को वापस बुलाने और आगे की जांच करने के बाद, इसे उच्च न्यायालय को भेज दिया। अपील पर 40.10.2011 को पुष्टि मामले और दर्ज किए गए अतिरिक्त सबूतों के साथ उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई की गई। उच्च न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों की सराहना करने के बाद, जिस क्रूर और वीभत्स तरीके से अपराध किया गया था, उसे देखते हुए मौत की सजा की पुष्टि की। हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी की वासना की संतुष्टि के लिए कम उम्र के लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया, जो हाई कोर्ट के मुताबिक, दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और मौत की सजा की पुष्टि की, जिसके खिलाफ ये अपीलें दायर की गई हैं।

6. श्री पी.सी. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है और सभी परिस्थितियों को मिलाकर केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि आरोपी उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों का दोषी नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत को स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है और पीडब्लू2, पीडब्लू3, पीडब्लू8 और पीडब्लू9 यह स्थापित नहीं करेगा कि पीड़िता को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य [के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 49

विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर सका कि आरोपी के घर से बरामद की गई वस्तुएं मृतक की थीं। यह बताया गया कि पीडब्लू1 और पीडब्लू6 के साक्ष्य पूरी तरह से अयोग्य थे और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि डीएनए प्रोफाइल के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से आरोपियों को फंसाने के लिए गढ़े गए हैं और उस संबंध में पीडब्लू10 और पीडब्लू14 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शंकर चिल्लागे ने प्रस्तुत किया कि नीचे की अदालतों सी ने पीडब्लू2, पीडब्लू3, पीडब्लू8 और पीडब्लू9 के साक्ष्यों की सही सराहना की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पीड़िता को आखिरी बार देखा गया था। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, आरोपी की कंपनी और अंतिम देखे गए सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी सिद्धांत पूरी तरह से संतुष्ट हैं। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि पीडब्लू 1 और पीडब्लू 6 के साक्ष्यों को निचली अदालतों द्वारा सही ढंग से सराहा गया है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तों के कब्जे से बरामद वस्तुएं मृतक की थीं। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने सहायक रासायनिक विश्लेषक, पीडब्लू 5 के साक्ष्य की सही सराहना की है, जिन्होंने डीएनए परीक्षण किया था और गवाही दी थी कि उन्होंने आरोपी के रक्त का नमूना प्राप्त किया था और रक्त प्रोफ़ाइल से प्रोफ़ाइल का मिलान किया था, जिसे भेजा गया था। एक्ज़िबिट 1 के रूप में यानी हाफ पैंट से वीर्य का दाग काटना और रिपोर्ट एक्ज़िबिट 38 प्रस्तुत किया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू5 के साक्ष्य को पीडब्लू12, पीडब्लू13, पीडब्लू15 और पीडब्लू16 के साक्ष्य के प्रकाश में सराहा जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि मृतक के गुदा स्मीयर से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल आरोपी से मेल खाता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डीएनए प्रोफ़ाइल निर्णायक रूप से इंगित करती

है कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध किया है। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने सही माना है कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और सही ढंग से मौत की सजा सुनाई गई है।

8. पीडब्लू 7, शोभा वैद्य, मृतक की मां, एक नौकरानी, अपने 10 साल के लापता बेटे का पता जानने के लिए कुछ दिनों से उत्सुकता से इधर-उधर दौड़ रही थी। लड़का दिनांक 10.1.2008 को स्कूल गया था और सामान्यतः वह शाम को लौट आता था, लेकिन उस दिन वह वापस नहीं लौटा। चूँकि कुछ दिनों तक लड़के का कोई पता नहीं चला, उसने 15.1.2008 को शाम लगभग 5.00 बजे शिकायत दर्ज कराई। पीडब्लू10 से पहले, अपराध शाखा, नागपुर से जुड़े पुलिस उप-निरीक्षक, जो सदर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। इस बीच, अभियुक्त के घर के पास रहने वाली एक महिला, पीडब्लू2, मैरी ने पीडब्लू10 को सूचित किया कि 9-10 साल की उम्र के एक लड़के का शव जूना कब्रिस्तान (पुराना कब्रिस्तान) के एक कुएं में तैरता देखा गया था। पीडब्लू 10 फिर घटनास्थल पर गया और फायर ब्रिगेड की सहायता से शव को कुएं से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पीडब्ल्यू 10

ने रिपोर्ट दर्ज कर धारा 377, 302 और 201 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया।

9. पीडब्लू 14, सदर पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस उप-निरीक्षक को जांच सौंपी गई थी। उस समय तक, आरोपी को 17.1.2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खुलासे पर, मृतक से संबंधित विभिन्न सामान आरोपी के घर से बरामद किए गए थे और उन्हें पंचों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया था। एक बक्से में छिपाकर रखा गया मृतक का स्कूल बैग बरामद कर लिया गया, जो काले रंग का था और उस पर गुलाबी धारियां थीं। पंचों की मौजूदगी में बैग खोला गया और उसमें बाल भारती की पाठ्यपुस्तक, गणित और अंग्रेजी की किताबें, दो नोटबुक, सभी पर मृतक का नाम लिखा हुआ पाया गया। इसके अलावा, आरोपी की एक बारमूडा पैंट और मृतक की एक जींस 17.01.2008 को बरामद की गई। आरोपी को मेडिकल जांच के लिए रेफर किया गया और 18.01.2008 को रक्त का नमूना लिया गया। एग्जीबिट 17 के तहत रक्त वीर्य और नाखून कतरन के नमूने लिए गए। आरोपी के बताने पर उसके द्वारा पहनी गई शर्ट, जो कि

एक पेड़ के पास पत्थर के नीचे छुपाई गई थी, दिनांक 22.01.2008 को बरामद की गई। जब्त किए गए लेखों को नागपुर में रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। एनालाइज़र की रिपोर्ट Exibits 91 और 92 पर हैं, जबकि DNA रिपोर्ट Exibits 35 -और 38 पर हैं। जांच पूरी करने के बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 377 और B 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष की ओर से, चौदह गवाहों से पूछताछ की गई और दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए गए और बचाव पक्ष की ओर से, किसी से भी पूछताछ नहीं की गई।

10. पीडब्लू2, मैरी, जो आयकर कार्यालय के सामने एक चाय की दुकान चलाती है, जो पुराने कब्रिस्तान के पास है, अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए जांच की गई कि लड़के को आरोपी की कंपनी में देखा गया था। उसने बताया कि वह अपने घर के ठीक सामने रहने वाले आरोपी को जानती है। उसने यह भी बताया कि 13.1.2008 को आरोपी उसकी दुकान पर आया और गुटका मांगा, जो उसने नहीं दिया। बाद में आरोपी के घर से करीब 11 साल के एक लड़के को भेजा गया, जिसने उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदा और उसी घर में लौट आया. आरोपी का पड़ोसी पीडब्लू 3 भी पुराने कब्रिस्तान के पास रहता है। उसने यह भी बताया कि उसने लड़के को 10.01.2008 और 11.01.2008 को आरोपी के साथ देखा था। पीडब्लू8, आरोपी की बहन, जो आरोपी के साथ उसके घर

में रहती थी, ने कहा कि उसने उपर्युक्त अवधि के दौरान और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आरोपी की कंपनी में लगभग 10 से 12 साल की उम्र के एक लड़के को देखा था। 12.01.2008 और 13.01.2008 की मध्य रात्रि में उसने आरोपी के कमरे से लड़के एफ की रोने की आवाज सुनी। आरोपी की पड़ोसी पीडब्लू9 ने आरोपी के साथ 10 साल की उम्र के एक लड़के को भी देखा और 12.01.2008 की आधी रात को उसने आरोपी के घर की तरफ से एक छोटे लड़के की रोने की आवाज सुनी।

11. हम गुजर चुके हैं. पीडब्लू 2, पीडब्लू 3, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 9 के साक्ष्य पूरी तरह से और, हमारे विचार में, वे भरोसेमंद और भरोसेमंद हैं।

52 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

हमारे विचार में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सफल रहा है कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. पीडब्लू 1 और पीडब्लू 6, क्रमशः एक्ज़िबिट 13 और एक्ज़िबिट 40 के पंचों की जांच अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के पैंट के साथ-साथ स्कूल बैग की बरामदगी को साबित करने के लिए की गई थी। आरोपी के घर में खाट के नीचे रखे एक बक्से से स्कूल बैग बरामद किया गया।

जब्ती पंचनाम एग्जिबिट्स 15 और 19 में आरोपी की निशानदेही पर जब्त की गई वस्तुओं का विवरण दिया गया है। स्कूल बैग में किताबें और नोट बुक थीं जिन पर मृतक का नाम लिखा था। पैंट और स्कूल बैग के साथ-साथ उसमें मौजूद किताबें स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि लड़का उस दिन आरोपी के साथ था। नतीजतन, आरोपी के कमरे में मृतक की मौजूदगी स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है और ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा उस आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्ष में भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. पीडब्लू4 वह डॉक्टर है जिसने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्शित 33) मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी और आंतरिक चोटों को इंगित करती है:

"बाहरी चोटें"

(1) गुदा चौड़ा हो गया है और तालु जैसा दिखाई देता है, पेरिओनल मार्जिन और म्यूकोसा सूजा हुआ दिखाई देता है, आंसू या विदेशी शरीर का कोई सबूत नहीं है।

(2) लिम्बस की स्थिति सीधी।

(3) 1.5 सेमी x 1.5 सेमी से 2 सेमी x 2 सेमी तक के आकार के माथे पर मौजूद कई खरोंचें (संख्या में 6)।

(4) दाहिने पार्श्व माथे पर 1.5 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी की गहराई का कटा हुआ घाव मौजूद है।

अनिल@एंथोनी अरिक्सस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य[के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 53

(5) 2 सेमी x 2 सेमी आकार के दाहिने प्रीऑरिक्यूलर क्षेत्र में संयुग्मित घर्षण।

(6) दाहिने चेहरे पर, 2 सेमी x 2.5 सेमी आकार की निचली आंख की पलक से 1.5 सेमी नीचे, घिसा हुआ घर्षण।

(7) ठुड्डी पर मौजूद सेंचुरियन का आकार 2 सेमी x 2.5 सेमी है।

(8) दाहिनी बांह पर घर्षण घर्षण मौजूद है, पूर्ववर्ती औसत पहलू, निचला 1/3 आकार 3.5 सेमी x 5 सेमी नीचे की ओर और दाहिनी ओर निर्देशित।

आंतरिक चोटें

(1) 4 सेमी x 5 सेमी x 0.5 सेमी आकार का दायां ललाट क्षेत्र।

(2) 5 सेमी x 4 सेमी x 0.5 सेमी आकार का दायां पैरिएटो-टेम्पोरल क्षेत्र।

(3) बायां पश्चकपाल क्षेत्र 4 सेमी x 4 सेमी x 0.5 सेमी आकार का।

मस्तिष्क, दाएं पैरिएटो-टेम्पोरल क्षेत्र में पार्टी लाल रंग की उपस्थिति।

14. पीडब्लू4 ने कहा है कि सभी आंतरिक चोटें बाहरी चोटों से मेल खाती हैं और वे मृत्यु-पूर्व थीं और आमतौर पर मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। पीडब्लू4 ने यह भी राय दी है कि मृतक के साथ शारीरिक संबंध होने की संभावना थी, हालांकि मौत का कारण सिर पर चोट थी। पीडब्लू4 ने यह भी कहा कि उसने एक्ज़िबिट 35 में डीएनए रिपोर्ट देखी थी और कहा था कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक के गुदा स्मीयर से एक मिश्रित डीएनए प्रोफ़ाइल मिलती है जो हाफ पैंट पर लगे वीर्य और पीड़ित के खून से मेल खाती है। पीडब्लू4 को डीएनए की एक अन्य रिपोर्ट भी दिखाई गई, जो आरोपी के नियंत्रण नमूने के रक्त के संबंध में थी और कहा गया कि रक्त का डीएनए प्रोफाइल मृतक के गुदा में पाए गए वीर्य के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि चोट संख्या 1, 3, 4 और 5 कठोर और कुंद वस्तु से संभव थी जबकि चोट संख्या 2 तेज धार से लगी थी।

54 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2014] 3 एस.सी.आर.

तथ्यों से साफ पता चलता है कि बर्बर तरीके से हवस पूरी करने के बाद उसे चुप कराने के लिए जानलेवा चोटें पहुंचाई गईं। सबूत मिटाने की कोशिश की गई जो साबित भी हुए. पीडब्लू4 ने चोट संख्या 1 के संबंध में

भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे गुदा के फैलाव के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और तालु जैसा प्रतीत होता है, पेरिअनल मार्जिन गुदा म्यूकोसा में सूजन दिखाई देती है, हालांकि आंसू या विदेशी शरीर का कोई सबूत नहीं है।

15. पीडब्लू5, सहायक रासायनिक विश्लेषक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, कलिना, मुंबई ने कहा कि उन्हें 24.1.2008 को क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नागपुर से पार्सल प्राप्त हुए थे और उन्होंने उसी दिन विश्लेषण शुरू किया था। उन्होंने कहा कि एक्ज़िबिट 1 आरोपी का डीएनए प्रोफ़ाइल है और एक्ज़िबिट 5 गुदा स्मीयर मृतक का है, जो मिश्रित प्रोफ़ाइल देता है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि Exibit1 वीर्य के दाग से प्राप्त प्रोफ़ाइल Exibit 5 गुदा स्मीयर से प्राप्त प्रोफ़ाइल से मेल खाती है और मृतक से एकत्र किए गए Exibit 4 रक्त के दाग गॉज से भी मेल खाती है। उसने कहा कि उसने दो परीक्षण किए, एक न्यूक्लियर शॉर्ट टैंडेम रिपीट (एसटीआर) और वाई शॉर्ट टैंडेम रिपीट (वाईएसटीआर)। पीडब्लू5 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने आरोपी के रक्त के नमूने प्राप्त किए और उस रक्त से प्राप्त प्रोफ़ाइल का एक्सिबिट्स 1 और 5 की प्रोफ़ाइल से मिलान किया और प्रोफ़ाइल मेल खा रही थी। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, पीडब्लू5 को आगे के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजे जाने के बाद वापस बुलाया गया था और उसने दोहराया कि उसने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के रक्त के नमूने का विश्लेषण किया था

और यह उस नमूने से मेल खाता था, जिसे भेजा गया था। एग्ज़िबिट 1 यानी हाफ पैंट से वीर्य का दाग काटना. उसने तदनुसार एक्ज़िबिट 38 के रूप में एक रिपोर्ट जारी की।

16. पीडब्लू 12, मेयो अस्पताल, नागपुर से जुड़े चिकित्सा अधिकारी की जांच यह साबित करने के लिए की गई थी कि उन्हें एक्सिबिट 75 में मांग के तहत आरोपी के रक्त के नमूने, जघन बाल, नाखून और वीर्य लेने की मांग प्राप्त हुई थी, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया था। डीएनए परीक्षण के साथ-साथ पार्सल को रासायनिक विश्लेषक के पास ले जाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए पीडब्लू15 और पीडब्लू 16 की भी जांच की गई।

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य[के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 55

रक्त के नमूने एकत्र करना, आदि। पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के साक्ष्य ए को पीडब्लू12, पीडब्लू15 और पीडब्लू16 के साक्ष्य के साथ पढ़ने पर, हमारा मानना है कि डीएनए परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था और गुदा स्मीयर डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है। वीर्य के धब्बे जो आरोपी की पैंट पर पाए गए थे और उनका मिलान आरोपी के नियंत्रण रक्त नमूने के साथ-साथ मृतक के रक्त नमूने से किया गया था।

17. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीएनए, एक अणु है जो सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध करता है। डीएनए जीनोटाइप किसी भी जैविक सामग्री जैसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अब, कई वर्षों से, डीएनए प्रोफाइल ने फोरेंसिक जांच पर भी जबरदस्त प्रभाव दिखाया है। आम तौर पर, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का डीएनए प्रोफाइल संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, तो आमतौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति समान है। डीएनए प्रोफ़ाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष परिणाम में भिन्नता प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

18. पीडब्लू5, डॉ. वर्षा राठौड़ ने कहा कि 1994 से वह सहायक रासायनिक विश्लेषक के रूप में काम कर रही थीं और उन्होंने डीएनए परीक्षण सहित हजारों नमूनों का विश्लेषण किया है। उसने कहा है कि उसने दो परीक्षण किए थे, एक एसटीआर और दूसरा वाईएसटीआर। दोनों परीक्षण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और परीक्षण करने वाले डॉक्टर की योग्यता पर भी सवाल नहीं उठाया गया है। नतीजतन, डीएनए परीक्षण रिपोर्ट को सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सका, जिससे पता चलता है कि मृत लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया था और धारा 377 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से किया गया है।

19. धारा 377 मुख्य रूप से लौंडेबाज़ी, गुंडागर्दी और पाशविकता के कृत्य तक ही सीमित है, जिसका उद्देश्य किसी पुरुष को दंडित करना है जब वह किसी पुरुष के साथ प्रकृति के आदेश के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है या, उसी तरह, एक महिला के साथ। सोडोमी को पेडरैस्टी कहा जाता है जब संभोग एक पुरुष और एक युवा लड़के के बीच होता है, यानी जब निष्क्रिय एजेंट एक युवा लड़का होता है। मोदी के मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान में कहा गया है कि यदि एक निष्क्रिय एजेंट सोडोमी, घर्षण का आदी नहीं है

गुदा के पास की त्वचा दिखाई देने की संभावना है और घाव बच्चों में सबसे अधिक चिह्नित होंगे, जबकि वयस्कों में वे लगभग अनुपस्थित हो सकते हैं, जब गुदा सहवास के लिए कोई प्रतिरोध नहीं होता है। गैल्स्टर के मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान का कहना है कि निष्क्रिय एजेंट में हालिया घाव, चोट, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन जैसे घाव देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 377 लिंग द्वारा गुदा में प्रवेश को दर्शाता है और अपराध स्थापित करने के लिए मामूली प्रवेश ही पर्याप्त है। पीडब्लू 4 ने स्पष्ट रूप से देखा है कि "गुदा चौड़ा हो जाता है और पाताल जैसा दिखाई देता है, पेरिओनल मार्जिन और म्यूकोसा सूजा हुआ दिखाई देता है"। डीएनए परीक्षण से यह भी साबित हुआ कि गुदा स्मीयर स्मीयर के दाग के डीएनए प्रोफाइल से

मेल खाता है, जो आरोपी के नियंत्रण नमूने से भी मेल खाता है। एक निष्क्रिय एजेंट की सहमति बिल्कुल भी बचाव नहीं है, लेकिन, मौजूदा मामले में, हालांकि एक सुझाव दिया गया था कि लड़के ने विरोध नहीं किया था, कुछ दिनों के लिए आरोपी की कंपनी में रहने का कोई मतलब नहीं है, वह एक है नाबालिग। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि, लड़के को पेडरैस्टी के अधीन करने के बाद, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।

20. पीडब्लू8 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने आधी रात के दौरान लड़के की रोने की आवाज़ सुनी थी और जब तक रोना कम नहीं हो गया, उसे नींद नहीं आई। पीडब्लू 8 कोई और नहीं बल्कि आरोपी की बहन है। उसने आरोपी के कमरे से लड़के की चीखें सुनीं। वह एक भरोसेमंद गवाह है और उसके पास आरोपी के खिलाफ कोई जवाब नहीं है। पीडब्लू9 ने यह भी कहा है कि वह उस दिशा में जाना चाहती थी जहां उसने चीखें सुनी थीं, हालांकि, अंधेरे ने उसे और अन्य लोगों को घटनास्थल की ओर बढ़ने से रोक दिया। सुनाई देने वाली चीखें स्पष्ट रूप से तेज़ आवाज़ में थीं, जो इंगित करती हैं कि आरोपी ने इस तरह के बर्बर कृत्य को अंजाम दिया था और अंततः लड़के की हत्या कर दी और बाद में शव को पुराने कब्रिस्तान के परिसर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया, जो कि उसके पीछे स्थित एक स्थान था। घर। इसलिए, निचली अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध मानसिक रूप से अत्यधिक भ्रष्टता दर्शाता है और

अत्यधिक विकृति दर्शाता है और इसलिए, अत्यधिक सजा की मांग की जाती है यानी आरोपी को तब तक गर्दन से लटकाया जाना चाहिए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। हमारी राय है कि आईपीसी की धारा 302, 377 और 201 के तहत मामला स्पष्ट रूप से बनाया गया है।

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य [के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 57

सवाल केवल सज़ा के संबंध में है और क्या वर्तमान मामला दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है, जिसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता है।

21. शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एससीसी 546 में, हमने मौत की सजा देते समय लागू किए जाने वाले विभिन्न सिद्धांतों बी पर चर्चा की है। उस मामले में, हमने उन मामलों का उल्लेख किया है जिनमें नाबालिग लड़कों और लड़कियों की हत्या के लिए इस न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई थी और ऐसे मामले जहां नाबालिग लड़कों और लड़कियों की हत्या के मामलों में मौत की सजा को बदल दिया गया था। शंकर किसनराव खाड़े (सुप्रा) में, हमने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 और मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470 और उसके बाद के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों का भी व्यापक रूप से उल्लेख किया है। शंकर किसनराव खाड़े (सुप्रा) में

निर्धारित परीक्षणों को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि तत्काल मामले में अपराध परीक्षण और आपराधिक परीक्षण आरोपी के खिलाफ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। फिर भी, हमें आरआर परीक्षण लागू करना होगा और जांच करनी होगी कि क्या समाज ऐसे अपराधों से घृणा करता है और क्या ऐसे अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोरते हैं और समुदाय के तीव्र और चरम आक्रोश को आकर्षित करते हैं।

22. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि पेडेरास्टी से पहले हुए इस प्रकार के अपराध बेहद क्रूर, विचित्र शैतानी और विद्रोही हैं, जो नैतिक ढांचे को झकझोर देते हैं। समाज, खासकर जब निष्क्रिय एजेंट नाबालिग हो। हाल ही में, इस न्यायालय ने सुरेश कुमार कौशल और अन्य बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य (2014) 1 सेकंड 1 में भी धारा 377 को रद्द करने से इनकार कर दिया है, भले ही ऐसे कृत्य सहमति से व्यक्तियों द्वारा किए गए हों।

23. आरोपी की उम्र अब करीब 42 साल है और जब उसने अपराध किया तब उसकी उम्र करीब 35 साल थी. हमने स्पष्ट रूप से पाया है कि अभियुक्तों के पक्ष में कोई राहत देने वाली परिस्थिति नहीं है। उम्र उनके पक्ष में कोई कारक नहीं है. 35 वर्ष की आयु तक, एक व्यक्ति पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर लेता है और यह पहचान सकता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा, और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह किसी भी

भावनात्मक या मानसिक तनाव में था और अपराध केवल उसकी वासना को संतुष्ट करने के लिए,

58 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

विकृत तरीके से किया गया था। आरोपी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा नहीं है, लेकिन लड़का नाबालिग, पूरी तरह से निर्दोष और असहाय था, पीडब्ल्यू 7 का इकलौता बेटा था। माँ, पीडब्लू7, एक घरेलू नौकरानी है और बेटा बुढ़ापे में उसकी देखभाल करता होगा और उसकी काफी मदद भी करता होगा। आरोपी की विकृत हवस को पूरा करने के लिए ही बेटे को बर्बरतापूर्ण वीभत्स तरीके से छीन लिया गया। पीडब्लू7, मां को बेटे का शव कुएं में तैरता हुआ देखना पड़ा। पीडब्लू8, आरोपी की बहन और पीडब्लू9, पड़ोसी, दोनों महिलाओं ने आधी रात के दौरान असहाय लड़के की चीखें सुनीं लेकिन दोनों असहाय थीं। पीडब्लू 8 अपने कमरे से बाहर नहीं जा सका क्योंकि वह बाहर से बंद था। पीडब्लू9, एक महिला घने अंधेरे के कारण आरोपी के घर नहीं जा सकी।

24. शंकर किसनराव खाड़े (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि नहीं की, भले ही पोस्टमार्टम में डी को सोडोमी का कृत्य बताया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 377 के तहत आरोपी पर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहा था, जिस पर टिप्पणी की गई थी इस न्यायालय द्वारा. लेकिन, जहां तक वर्तमान मामले का सवाल

है, धारा 302 और 377 के तहत अपराध पूरी तरह से स्थापित हो चुका है और अपराध परीक्षण और आपराधिक परीक्षण दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब, हमें आरआर टेस्ट लागू करना होगा।

25. हम बता सकते हैं कि बचन सिंह के मामले (सुप्रा) और मच्छी सिंह के मामले (सुप्रा) में जो कहा गया है, उसके अलावा इस न्यायालय ने ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ एफ-लार्याना (1999) 3 एससीसी 19, राज्य जैसे विभिन्न मामलों में कहा है। के ऊपर। बनाम सत्तन (2009) 4 एससीसी 736, संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498, ने माना कि अदालत को मौत की सजा देने के लिए विशेष कारण बताने चाहिए, इसलिए, आरआर टेस्ट।

आरआर टेस्ट

26. आर-आर टेस्ट, हम पहले ही शंकर किसनराव खाड़े मामले (सुप्रा) में आयोजित कर चुके हैं, यह समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है न कि "न्यायाधीश-केंद्रित", यानी कि क्या समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सज़ा देने को मंजूरी देगा या नहीं।

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य[के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 59

उस परीक्षण को लागू करते समय, अदालत को नाबालिग लड़कियों, बौद्धिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़कियों, शारीरिक विकलांगता से पीड़ित नाबालिगों, वृद्ध और अशक्तों के यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे कुछ प्रकार के अपराधों के प्रति समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और घृणा जैसे विभिन्न कारकों पर गौर करना होगा। महिला, आदि। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में आर-आर टेस्ट को संतुष्ट पाया गया है, जैसे बंटू बनाम यूपी राज्य। (2008) 11 एससीसी 113, जिसमें इस अदालत ने एक ऐसे मामले में मौत की सजा की पुष्टि की जहां पांच साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस न्यायालय ने देखा कि पीड़ित एक मासूम बच्चा था और हत्यारा एक प्रभावशाली स्थिति में था, जिसे न्यायालय ने मृत्युदंड के पुरस्कार को उचित ठहराने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पाया। शिवाजी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 15 सेकंड 269, एक ऐसा मामला था जहां एक विवाहित व्यक्ति जिसके तीन बच्चे थे, जो मृतक के परिवार को जानता था, ने 9 साल की एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, इस अदालत ने पुष्टि की उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा. मो. मन्नान बनाम बिहार राज्य (2011) 5 सेकंड 317, एक ऐसा मामला था जहां 7 साल की एक नाबालिग लड़की का 42-43 साल की उम्र के आरोपी द्वारा अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। इस न्यायालय ने माना कि वह समाज के लिए खतरा होगा और आगे भी रहेगा और उसे

सुधारा नहीं जा सकता और इसलिए मौत की सजा की पुष्टि की गई। राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 4 एससीसी 37 एक ऐसा मामला था जहां 31 साल के आरोपी द्वारा 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस अदालत ने उस क्रूर तरीके पर गौर किया जिसमें अपराध किया गया था और नाबालिग लड़की को जो दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ी थी। इस कोर्ट ने मौत की सज़ा की पुष्टि की.

27. हरेश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 12 एससीसी 56 में, इस न्यायालय ने कहा कि किसी दिए गए मामले में मौत की सजा दी जा सकती है, जहां पीड़ित निर्दोष बच्चे और असहाय महिलाएं हैं, खासकर जब अपराध किया गया हो बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से जो बेहद क्रूर, वीभत्स, शैतानी और विद्रोही है। रवीन्द्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य (2011) 2 एससीसी 490, सुरेंद्र कोफी बनाम

60 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 3 एस.सी.आर.

यूपी राज्य और अन्य (2011) 4 एससीसी में इस न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ लिया जा सकता है 80 और सुदाम @ राहुल कनीराम जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 7 एससीसी 125।

28. इस न्यायालय ने महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य बी (1987) 3 एससीसी 80 में उदार दृष्टिकोण अपनाने और उचित सजा न देने की प्रथा

की निंदा करते हुए कहा कि आरोपी को चरम सीमा से बचने की अनुमति देना न्याय का मजाक होगा। ऐसे सबूतों और क्रूर कृत्यों का सामना होने पर कानून का दंड। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को कम सज़ा देना इस देश की न्याय प्रणाली को संदिग्ध बनाना होगा और आम आदमी का अदालतों पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे मामलों में, वह सुधारात्मक शब्दजाल की तुलना में निवारण की भाषा को अधिक समझता और सराहता है। बंटू (सुप्रा) में, यह न्यायालय सेवका पेरुमल बनाम टी.एन. राज्य के फैसले पर भरोसा कर रहा है। (1991) 3 डी एससीसी 471 इस प्रकार देखा गया:

> "इसलिए, अपर्याप्त सजा देने के प्रति सहानुभूति न रखने से न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान होगा और कानून की प्रभावकारिता में जनता का विश्वास कम होगा, और समाज इस तरह के गंभीर खतरों को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता है। इसलिए, यह हर अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया या किया गया, आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा देना।
>
> इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आपराधिक कानून में समाज पर उचित सजा न देने के प्रभाव को ध्यान में रखते

हुए प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार सजा प्रदान करने में आनुपातिकता के नियम का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता होती है।

- "दुर्लभतम मामला" तब आता है जब एक दोषी समाज के सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा और ख़तरा बन जाता है। जहां कोई आरोपी किसी भी क्षण उकसावे में आकर कार्रवाई नहीं करता है और वह जानबूझकर योजनाबद्ध अपराध में शामिल हो जाता है और उसे सावधानीपूर्वक निष्पादित करता है, यदि इसे सावधानीपूर्वक निष्पादित किया जाए, तो ऐसे भयानक अपराध के लिए मौत की सज़ा सबसे उपयुक्त सज़ा हो सकती है।"

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य[के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 61

29. हम संकेत दे सकते हैं, शंकर किसनराव खाड़े मामले (सुप्रा) के विपरीत, इस मामले में आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध पूरी तरह से साबित हो गया है और धारा 302 आईपीसी के तहत भी अपराध साबित हुआ है। भारतीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय समाज भी समलैंगिकता, अप्राकृतिक यौन संबंध, यानी एक पुरुष और एक नाबालिग लड़के या

लड़की के बीच शारीरिक संबंध से घृणा करता है। जब पीड़िता नाबालिग हो, तो सहमति बचाव नहीं है, भले ही वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध पर कुछ हलकों में जो भी विचार व्यक्त किए गए हों।

सुधार और पुनर्वास

30. अभियुक्त के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह समाज के लिए खतरा नहीं होगा। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि आरोपी, जिसकी उम्र 42 वर्ष है, के सुधार या पुनर्वास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और राज्य ने पुनर्वास की असंभवता साबित करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है।

31. बचन सिंह (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है, "संभावना है कि अभियुक्त हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा क्योंकि इससे समाज को लगातार खतरा होगा", एक प्रासंगिक परिस्थिति है, जिसे बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए वाक्य के निर्धारण में. इसे आगे संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार (सुप्रा) में व्यक्त किया गया। कई बार सजा का निर्धारण करते समय अदालतें किसी मामले विशेष के तथ्यों को देखते हुए यह मान लेती हैं कि आरोपी समाज के लिए खतरा होगा और उसके सुधार व पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, जबकि ऐसा होता है। उन कारकों का पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है, और राज्य

अभियुक्तों के सुधार और पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। किसी दिए गए मामले में अदालतें जिन तथ्यों पर विचार करती हैं, वे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए, जैसा कि पहले ही कहा गया है, अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि आपराधिक अदालतें, दोषी ठहराए जाने के बाद, आईपीसी की धारा 302 जैसे अपराधों से निपटते समय, उपयुक्त मामलों में, यह निर्धारित करने के

लिए एक रिपोर्ट मांग सकती हैं कि क्या आरोपी को सुधारा जा सकता है या पुनर्वास किया जा सकता है, जो तथ्यों पर निर्भर करता है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

32. विद्वान वकील ने यह भी बताया कि आरोपी ने लड़के का अपहरण नहीं किया था, जो स्वेच्छा से आया और उसके साथ रहा। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और आम तौर पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, मौत की सजा शायद ही कभी दी जाती है। अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया गया, जैसे महाराष्ट्र राज्य बनाम मानसिंह (2005) 3 एससीसी 131 और बंटू बनाम मध्य प्रदेश राज्य। (2001) 9 एससीसी 615। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी

संदर्भ दिया जहां मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, जैसे आलोक नाथ दत्ता बनाम पश्चिम डी बंगाल राज्य (2007) 12 एससीसी 230, सहदेव बनाम राज्य के ऊपर। (2004) 10 एससीसी 682, स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 12 एससीसी 288, शंकर किसनराव खाड़े (सुप्रा), हरेश मोहनदास राजपूत (सुप्रा), राजेश कुमार बनाम राज्य (2011) 13 सेकंड 706, अमित बनाम। यूपी राज्य. (2012) 4 सेकंड 107, आदि।

33. पीडब्लू 8 और पीडब्लू 9 ने 12.01.2008 की आधी रात के दौरान नाबालिग लड़के की रोने की आवाज सुनी और उनके साक्ष्यों को देखने के बाद वे हमारे कानों में गूंज गईं। चोट संख्या 1, 3 से 5 कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं, जबकि चोट संख्या 2 तेज धार वाली धार से लगी थीं और चोट संख्या 6 कठोर और दाने वाली वस्तु से लगी थीं, इसके अलावा, धारा 377 के तहत भी अपराध हुआ। साबित हुआ. हत्या बेहद क्रूर, वीभत्स, शैतानी और नृशंस तरीके से की गई थी और आरोपी दबंग स्थिति में था और पीड़ित एक मासूम लड़का था, जो अपनी मां का इकलौता बेटा था। अपराध को अंजाम देने के समय आरोपी की उम्र 35 साल थी यानी वह पूरी तरह से परिपक्व व्यक्ति था। पीडब्लू7 के इकलौते बेटे, उसकी मां, की जान एक वीभत्स और बर्बर तरीके से ले ली गई, जो न केवल न्यायिक चेतना बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी चुभती है।

अनिल @एंथनी अर्कस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य [के.एस. राधाकृष्णन, जे.] 63

34. विधायी नीति को सीआरपीसी की धारा 354(3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 235(2) ए से समझा जा सकता है, कि जब दोषी भ्रष्टता के अनुपात को मान लेता है, तो न्यायालय को धारा 354(3) के अर्थ के भीतर विशेष कारण बताने होते हैं।) मौत की सजा देने के लिए। विधायी नीति यह है कि जब विशेष कारण मौजूद होते हैं, जैसे कि तत्काल मामले में, न्यायालय को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है और उचित सजा देकर विधायी नीति का सम्मान करना होता है, यही लोगों की इच्छा है। हमारा विचार है कि पहले से ही भुगती गई सजा के अलावा, बिना छूट के तीस साल की अतिरिक्त अवधि की कैद, मौत की सजा के बजाय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पर्याप्त सजा होगी। तदनुसार आदेश दिया गया।

35. तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

डी.जी.

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन मीना [(आर.जे.एस.) RJ00617] द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।